



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-७] रुड़की, शनिवार, दिनांक १६ दिसम्बर, २००६ ई० (अग्रहायण २५, १९२८ शक सम्बत) [संख्या-५०

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चंदा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु०
भाग १—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	3075	—
भाग १-क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	493-501	1500
भाग २—आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	175-176	1500
भाग ३—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइल एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग ४—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	69	975
भाग ५—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	—	975
भाग ६—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग ७—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	—	975
भाग ८—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	—	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि	—	1425

भाग १

विज्ञप्ति—आवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

परिशिष्ट—ख

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2006 ₹०

संख्या 1693 / VIII / 441—क०रा०बी०यो०/ 2002—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए श्री राज्यपाल उत्तरांचल, मुख्य भेषजिक (राजपत्रित) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तरांचल मुख्य भेषजिक (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2006

भाग एक—सामान्य

१—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (१) यह नियमावली उत्तरांचल मुख्य भेषजिक (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2006 कहलायेगी।
- (२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

२—सेवा की प्रारिथ्ति :

उत्तरांचल मुख्य भेषजिक (राजपत्रित) सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह “ख” के पद समाविष्ट हैं।

३—परिमाणाएँ :

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में—

- (क) ‘नियुक्ति प्राधिकारी’ का तात्पर्य सचिव, श्रम, उत्तरांचल शासन से है;
- (ख) ‘संविधान’ का तात्पर्य “भारत का संविधान” से है;
- (ग) ‘सरकार’ का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;
- (घ) ‘राज्यपाल’ का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (ङ) ‘सेवा का सदस्य’ का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद से है;
- (च) ‘सेवा का तात्पर्य’ उत्तरांचल मुख्य भेषजिक (राजपत्रित) सेवा से है;
- (छ) ‘मौलिक नियुक्ति’ का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
- (ज) ‘भर्ती का वर्ष’ का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो—संवर्ग

४—(१) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(२) जब तक कि उपनियम (१) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी :—

क्रमांक	पंदनाम	स्थायी	अस्थायी	योग
1-	मुख्य भेषजिक (राजपत्रित)	03	—	03

परन्तु—

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ या आस्थगित रख सकता है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।
- (2) राज्यपाल समय-समय पर अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन-भर्ती

5—भर्ती का श्रोत :

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :—

(2) मुख्य भेषजिक—मौलिक रूप से नियुक्त भेषजिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

6—आरक्षण :

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार—पदोन्नति की प्रक्रिया

7—रिक्तियों का अवधारण :

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

8—प्रोन्नति की प्रक्रिया/विभागीय चयन समिति के माध्यम से :

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 के अनुबन्धों के अनुसार गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली के अनुसार तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, विभागीय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) विभागीय चयन समिति उगनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) विभागीय चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूचियां तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पांच—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

9—नियुक्ति :

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें नियम-8 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसाकि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाये।

10—परिवीक्षा :

(1) मौलिक रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्ति किए जाने पर मुख्य भेषजिक को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विभिन्निष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाये।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाए, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

11—स्थायीकरण :

उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

12—ज्येष्ठता :

किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग ४—वेतन इत्यादि

13—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत् हैं :—

पद का नाम	वेतनमान
-----------	---------

मुख्य भेषजिक (राजपत्रित)	5000—8000
--------------------------	-----------

14—परिवीक्षा अवधि में वेतन :

(1) मूल नियमों (फण्डामेंटल रूल्स) में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी यदि उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, वेतन सुसंगत मूल नियमों (फण्डमेंटल रूल्स) द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सामान्यता सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग सात—अन्य उपबन्ध

15—पक्ष समर्थन :

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अन्यर्थी की ओर से अपनी अन्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास, उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

16—अन्य विषयों का विनियमन :

ऐसे विषय जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया: लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

17—सेवा शर्तों में शिथिलता :

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्य पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

18—व्यावृत्ति :

इस नियमावली में किसी बात को कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

एस० राजू,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1693/Labour Employment/441-E.S.I./2002, dated September 27, 2006 for general information:

NOTIFICATION

September 27, 2006

No. 1693/Labour Employment/441-E.S.I./2002—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution and in supersession of all rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Chief Pharmacist (Gazetted) Service :—

UTTARANCHAL CHIEF PHARMACIST (GAZETTED) SERVICE RULES, 2006

PART-I

General

1. Short Title and Commencement :

- (1) These Rules may be called the Uttaranchal Chief Pharmacist (Gazetted) Service Rules, 2006.
- (2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service :

The Chief Pharmacist (Gazetted) Service is a State service comprising group "B" posts.

3. Definitions :

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

- (a) "Appointing Authority" means the Secretary, Labour, Uttaranchal Government;
- (b) "Constitution" means the Constitution of India;
- (c) "Government" means the State Government of Uttaranchal;
- (d) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;
- (e) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;
- (f) "Service" means Uttaranchal Chief Pharmacist (Gazetted) Service;
- (g) "Substantive appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rules and if there are no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;
- (h) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART-II

Cadre

4. (1) The strength of the service and each category of posts therein shall be as such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below:--

Sl. No.	Name of the Posts	Permanent	Temporary	Total
1.	Chief Pharmacist (Gazetted)	03	--	03

Provided That--

(1) The appointing authority may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.

(2) The Governor may create such additional temporary or permanent posts, as he may consider proper.

PART-III

Recruitment

5. Source of Recruitment :

(1) Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :--

(2) Chief Pharmacist--By promotion through the departmental selection committee from amongst substantively appointed Pharmacists who have completed at least twelve years service as such on their respective posts on the first day of July of the year of recruitment.

6. Reservation :

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART-IV

Procedure for Recruitment

7. Determination of Vacancies :

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule--6.

8. Procedure for Recruitment by promotion through the Departmental Selection Committee :

(1) Recruitment by promotion to the posts shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit through the Departmental Selection Committee, which is formed in accordance with the provision of the formation of Uttarakhand Departmental Promotion Committee (on Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection (on Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules & place the same before the Departmental Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Departmental Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records referred to in sub-rule (2) and if it considers necessary, it may interview the candidate also.

(4) The Departmental Selection Committee shall prepare a list of selected candidates and shall forward them to the appointing authority.

PART-V

Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

9. Appointment :

(1) The appointing authority shall make appointment by taking the name of candidate in the order in which they stand in the lists prepared under Rule-8.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

10. Probation :

(1) A person on substantive appointment or on deputation to the post of Chief Pharmacist shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post.

(4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service on any post included in the cadre or any other equivalent or higher posts to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

11. Confirmation :

Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if--

- (a) his work & conduct are reported to be satisfactory,
- (b) his integrity is certified, and
- (c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

12. Seniority :

The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

PART--VI**Pay etc.****13. Pay scale :**

(1) The scales of pay permissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given below :--

Name of the posts	Pay Scale
Chief Pharmacist (Gazetted)	5000-8000

14. Pay during probation :

(1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government Service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service & second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART--VII**Other Provisions****15. Canvassing :**

No recommendations either written or oral other than those required under the rules applicable to post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support, directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

16. Regulations of other matters :

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the services shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

17. Relaxation from the conditions of service :

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

18. Savings :

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

S. RAJU,
Secretary.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2006 ई० (अग्रहायण 25, 1928 शक सम्वत्)

भाग १—क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, चम्पावत
स्थानान्तरण पर कार्यभार छोड़ने का प्रमाण—पत्र

18 नवम्बर, 2006 ई०

संख्या 649/एक-१०-२००६-प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत का पदभार माननीय उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल के नौटिफिकेशन नं०-१६२/यू०६८०सी०/एडमिन०६/२००६, दिनांक 18-11-2006 के अधीन, प्रोन्नत होने पर जैसा यहां व्यक्त किया गया है, दिनांक 18 नवम्बर, 2006 के अपराह्न में छोड़ दिया है।

मुक्त अधिकारी

यू० एस० नवियाल,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चम्पावत।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह० अस्पष्ट

जनपद न्यायाधीश,

चम्पावत।

कार्यालय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, संभाग पौड़ी
कार्यालयादेश

08 नवम्बर, 2006 ई०

संख्या 98/प्रशासन/प्रवर्तन—लाईसेंस/06—श्री कीरत सिंह, पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी पदमपुर सुखरी कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल का लाईसेंस सं० के०-१७६/के०टी०डब्लू/२००१ इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन पौड़ी ने अपने पत्र सं० २१७५/लाईसेंस/०६, दि० १९-०९-२००६ के द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त वाहन चालक के द्वारा संचालित वाहन सं० यू०६०-१२-३९५५ जीप टैक्सी का चालान प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा क्रमशः दि० १४-१२-२००५, ०२-०४-२००६, २२-०६-२००६ को वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां ढोने तथा वाहन में सवारियां लटका कर संचालित करने में किये गये हैं। वाहन चालक द्वारा निरंतर यातायात नियमों का

उल्लंघन किया जा रहा है। सहारो संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन चालक को इस कार्यालय के पत्र सं074/प्रशासन/प्रवर्तन-लाईसेंस/06, दि 09-10-2006 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भौंका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय के उपरोक्त पत्र के संदर्भ में दि 07-11-2006 को इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा बार-बार की जा रही अनियमितताओं के लिये मैं सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं० के०-१७६/के०१०८८/२००१ को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की घारा 22 (I) के अन्तर्गत एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से तीन माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूँ।

४० (अस्पष्ट),

संभागीय परिवहन अधिकारी,
पौड़ी।

निदेशालय लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल

23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून

प्रभार प्रभाण—पत्र

10 जूलाई, 2006 ₹०

संख्या 12343 / निरोहो / 15(18) / वैष्णवी / 2006-2007-प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 12148 / निरोहो / 15(18) / वैष्णवी / 2006-2007, दिनांक 21 जून, 2006 के अनुपालन में श्रीमती प्रतिमा पैन्चली, उप निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल के दिनांक 26-06-2006 से 07-07-2006 तक अर्जित अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप उप निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, के पद का कार्यभार जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 10-07-2006 के पूर्वान्ध में ग्रहण किया।

ह० (अस्पष्ट),
एल० एन० पंत,
मुख्य अधिकारी

४० (अस्पष्ट),
प्रतिमा पैन्यूली,
मोचक अधिकारी।

पी०एस०य० (आर०ई०) 50 हिन्दी गजट/627-भाग 1-क-2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम प्रकाशक-उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2006 ई० (अग्रहायण 25, 1928 शक समवत्)

माग ३

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़—पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइल एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय, पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा

संशोधित सूचना

08 सितम्बर, 2006 ई०

पत्रांक 122/प०निर्वा०/उपपुनाव/2006—पंचायत उप निर्वाचन माह सितम्बर, 2006 को सम्पादित करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 113/प०निर्वा०/उप चुनाव/2006, दि० 05 सितम्बर, 2005 के साथ संलग्न की गई संलग्निका प्रारूप—18 के प्रथम पंक्ति में 'सदस्य ग्राम पंचायत' के स्थान 'सदस्य जिला पंचायत' के उप निर्वाचन एवं कॉलम सं० ३ 'ग्राम पंचायत का नाम एवं वार्ड संख्या' के स्थान पर 'सदस्य जिला पंचायत का वार्ड सं० एवं नाम' अंकित होना है। अतः उक्तानुसार संलग्निका के प्रारूप 18 को संशोधित समझा जाय।

ह० (अस्पष्ट),
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन
अधिकारी (प०),
अल्मोड़ा।

पी०एस०य०० (आर०ई०) ५० हिन्दी गजट/६२७—माग ३—२००६ (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।